य एषु सुप्तेषु जागर्ति नई दिल्ली . रविवार . 03 अप्रेल 2016 SUNDAY चैत्र कृष्ण पक्ष दशमी/एकादशी संवत् 2072 patrika.com

राजस्थान पत्रिका

सूखता पानी, बरसती आफत : गर्मी की दस्तक के साथ सिमट रहे हैं देश में जलस्रोत

...तो जल बिन तरसेगा कंठ

जल ही जीवन है। बिन पानी सब सून। जीवन के लिए जरूरी ये अमृत पाताल के पैंदे में जा पहुंचा है। गर्मी की दस्तक के साथ ही कंठ सूखने लगे हैं। जलस्रोत रीत रहे हैं। इंसानी लालच ने पानी का अतिदोहन कर हालात को और भी भयावह बना दिया है। बिना पानी पृथ्वी पर हमारा अस्तित्व नहीं होगा। इस अमूल्य निधि को सहेज कर रखना है। वैश्विक महाशक्ति बनने के लिए हम दावे कर रहे हैं पर दूसरी तरफ देश के ग्रामीण इलाकों में आज भी महिलाएं मीलों का सफर तय कर पानी लाती हैं। जल संरक्षण के सरकारी दावे कागजों की नौका के समान हैं। केंद्र सरकार 4 अप्रेल से जल सप्ताह (वॉटर वीक) मना रही है। ऐसे सरकारी समारोह पूर्व में भी होते रहे हैं, लेकिन बेनतीजा। कागजों में सिमट जाते हैं वादे और दावे। हमारे पास आज बामुश्किल गुजारे लायक जल है, लेकिन कल क्या होगा...

...तरस रहे बच्चे

नियोजित जल संसाधनों के अभाव से बड़ी आबादी जूझ रही है। बढ़ते निजीकरण, औद्योगिक व मानवीय अपशिष्टों से पेयजल संकट बढ़ा है। आज 10 करोड़ घरों में बच्चों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। इनमें हर दूसरा बच्चा कुपोषित है।

बीमारी की जड़

वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में 21 फीसदी संक्रामक बीमारियां दूषित पानी की वजह से होती फ्लोराइड, आर्सेनिक, लेड (सीसा) और यूरेनियम तक पानी में घुला है। बड़ी आबादी पेट के संक्रमण से लेकर कैंसर तक की चपेट में है।

30% अधिक दोहन, वर्षाजल पुनर्भरण की तुलना में

हर दस में से एक भारतीय के पानी में रासायनिक प्रदूषण

देश में 85 फीसदी पेयजल भूमिगत जलस्रोतों से प्राप्त होता है

70 हजार करोड़ रु. जल मिशन पर खर्च, 3 लाख करोड़ और चाहिए

18% ग्रामीण आबादी के पास ही शुद्ध पानी उपलब्ध है जबकि 41 फीसदी ग्रामीणों के पास हैं मोबाइल फोन

20% ग्रामीण आबादी देश की ऐसी है जो असुरक्षित जलस्रोतों पर निर्भर

3 लाख बच्चे मरते हैं दुनिया में हर साल दूषित पानी पीने से

जेब भी रीतेगी...

तीन-चौथाई रोजगार हैं पानी पर निर्भर

निहार गोखले

पानी की कमी को आप केवल प्यास तक ही सीमित न करें। ये आपकी जेब को भी रीत सकती है। पानी की कमी के कारण खाद्यानों के उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव तो पड़ता ही है, ये रोजगार पर भी असर डालता है। आर्थिक विकास पर भी पानी की अनुपब्धता रोक लगाती है। इस वर्ष विश्व जल दिवस पर यूनेस्को ने जल-रोजगार गठजोड़ (वॉटर-जॉब्स नेक्सस) नामक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के तीन-चौथाई रोजगार पानी पर सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार अगले 3 साल में पानी की कमी से कई तरह के व्यवसाय पानी की कमी के कारण प्रभावित होंगे। 2015 में वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम ने पानी की कमी को अगले दशक का सबसे बड़ा खतरा बताया था।

2.8 अरब पर असर

दुनिया भर में पानी पर 2.8 अरब रोजगार निर्भर हैं। इनमें से 1.6 अरब यानी लगभग 42 फीसदी रोजगारों की जीवनरेखा ही पानी है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार इन रोजगारों में कृषि, मत्स्य और ऊर्जा उत्पादन शामिल है।

4.75 करोड़ कामगार

विश्व के औद्योगिक सेक्टर में 4.75 कामगार संबंधी रोजगार पानी की उपलब्धता पर पूर्ण आश्रित हैं। ये आंकड़ा विश्व के औद्योगिक रोजगार का 30 फीसदी है। इसमें फूड प्रोसेसिंग, टैक्सटाइल्स और फार्मा इंडस्टीज शामिल है।

अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्था के अनुसार पानी की कमी से दुनिया की 45 फीसदी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम ने भी इस बारे में चेताया है।

36% आंशिक निर्भर

दुनिया के कुल कामगारों में से 1.1 अरब यानी 36 फीसदी आंशिक रूप से पानी की उपलब्धता पर निर्भर है। इसमें शामिल है पेपर निर्माण, रबर, प्लास्टिक और निर्माण सेक्टर। लगभग 60 फीसदी औद्योगिक और सर्विस सेक्टर की 30 फीसदी नौकरियां इसमें शामिल हैं।

45% जीडीपी पर खतरे की आशंका

अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्था के अनुसार पानी की कमी से दुनिया भर की 45 फीसदी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। कार्बन डिस्क्लोजर रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 405 कंपनियों के सर्वे में पानी की कमी से 2.5 अरब डॉलर के नुकसान की आशंका जताई गई है।

...6 माह में सूख जाएंगे जलस्रोत!

02 हजार अरब लीटर पेयजल की कमी

देश के 91 प्रमुख जलस्रोतों की 17 मार्च, 2016 की साप्ताहिक समीक्षा में उपलब्ध जल कम पाया गया। 43 अरब क्यूबिक मीटर पानी शेष है। प्रत्येक भारतीय की रोज की पानी की खपत 200 लीटर मानें तो ये 6 महीने में खत्म हो जाएगा।

मांग और आपूर्ति में बढ़ता अंतर

843 अरब क्यूबिक मीटर पानी चाहिए 2025 में

सरकार ने संसद में वर्ष 2015 में पेश रिपोर्ट में बताया कि देश में 1,123 अरब क्यूबिक मीटर पानी की सालाना उपलब्धता है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार 2050 तक देश में 1,180 अरब क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत होगी।

देश में 7.6 करोड़ लोग स्थायी पेयजल स्रोतों से वंचित हैं

3/4 ही पानी शेष है जलस्रोतों में पिछले 10 साल की तुलना में

एक तिहाई घरों में पाइपलाइन कनेक्शन

29 फीसदी भारतीय घरों में पेयजल पाइप कनेक्शन

नेशनल सैंपल सर्वे डाटा के निष्कर्षों के अनुसार 16 फीसदी ग्रामीण घरों में ही पेयजल के लिए पाइपलाइन कनेक्शन हैं जबकि शहर में 54 फीसदी घरों में ये सुविधा उपलब्ध है। केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत वर्ष 2017 तक देश के 55 फीसदी ग्रामीण घरों तक पाइपलाइन कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

संवैधानिक हक है पानी

सरकारी जिम्मा

केरल हाईकोर्ट ने वर्ष 1990 में अपने एक आदेश में अनुच्छेद 21 के संदर्भ में साफ पानी को नागरिकों का हक बताया था।

कोर्ट के अनुसार संविधान प्रदत्त जीने के अधिकार में स्वच्छ पानी और हवा भी शामिल है।

बंबई हाईकोर्ट ने भी वर्ष 2014 के अपने एक फैसले में पानी को नागरिकों का हक बताया।

यूनेस्को ने भी पानी को जीने के अधिकार के तहत बुनियादी अधिकार घोषित किया था।

लातूर का कसूर

पानी की किल्लत के चलते महाराष्ट्र के लातूर जिले में हैंडपंपों व जलस्रोतों के आसपास धारा 144 लगाई है।

हालात ये हैं कि लातूर जिले में 30 दिन में एक बार ही पानी की सप्लाई होती है।

वर्ष 2015 के मानसून के दौरान लातूर का मुख्य बांध एक फीसदी ही भर पाया था।

महाराष्ट्र सीएम रहे विलासराव व पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटील का गृहजिला है लातूर।

14 फीसदी कम बारिश हुई देश में वर्ष 2015 के मानसून के दौरान

80 फीसदी वर्षा जल देश में बहकर समुद्र में जाता है

1170 मिमी वार्षिक वर्षा होती है देश में, अधिकांश मानसून में

3 गुना उत्सर्जन

पैसिफिक इंस्टीट्यूट के मुताबिक अमरीका में 1 टन मिनरल वाटर बॉटल बनाने में 3 टन कार्बन उत्सर्जन होता है।

एक लीटर मिनरल वाटर बनाने पर 5 लीटर साफ पानी खर्च करना पड़ता है।

भारत में बोतलबंद पानी उद्य लगभग 100 कंपनियां और 1200 बाटलिंग प्लांट हैं।

दुनिया भर में हर साल बोतलबंद पानी खरीद पर लगभग 100 अरब डालर खर्च किया जाता है।

जांच ही नहीं

भारतीय मानक ब्यूरो के पास बोतलबंद पानी की जांच की कोई व्यवस्था नहीं है।

सीएसई के शोध में बोतलबंद पानी में मैलेथियॉन, डीडीटी, ऑर्गेनोक्लोरीस जैसे कैंसर जनक कीटनाशक पाए गए।

वर्ष 2018 तक देश में मिनरल वॉटर इंडस्ट्री 160 अरब रुपए की हो जाने का अनुमान है।

अमरीकी खाद्य प्रशासन के अनुसार 40 फीसदी बोतलबंद पानी असुरक्षित होता है।

ये भी कारण

बदला बारिश का पैटर्न

घटते जल स्तर के बड़े कारण और बढ़ते शहरीकरण में जल संरक्षण के क्या खास उपाय हों, बता रहे हैं, **सीएसई के उपनिदेशक, चंद्रभूषण...**

भारत में भूजल स्तर के नीचे जाने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, भूजल पर बहुत ज्यादा निर्भरता बढ़ना। दूसरा, बारिश के पैटर्न में तेजी से बदलाव आना। अब मानसून के दिन कम होते जा रहे हैं और जब बारिश होती है तो बहुत तीव्र होती है। इसके कारण अधिकांश पानी बेकार बह जाता है। पहले बारिश की गति मॉडरेट रहती थी जिससे पानी रुकता था और जमीन में ज्यादा रिचार्ज होता था।

ये हों उपाय

झील, तालाब ही बचाएंगे

जितनी मात्रा में पानी का दोहन हो रहा है, उस मात्रा में भूजल रिचार्ज नहीं हो रहा है। कंक्रीट के जंगलों में पानी रोकने के इंतजाम नहीं किए गए।

आज रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की सख्त जरूरत है। खासतौर पर शहरों में तो पानी रोकने का यही बड़ा जरिया है। पर उस पर बहुत कम काम हो रहा है। बाहरी इलाकों, गांवों में तालाब, झीलों और जोहड़ का फिर निर्माण करना होगा। क्योंकि इनके जरिए ही अधिक गति से होने वाली बारिश को रोका जा सकता है, जिससे भूजल रिचार्ज हो पाएगा। साथ जितना हो सके, वैटलैंड की व्यवस्था रहनी चाहिए।

नहीं चेते तो...

...फिर बिन पानी सब सून

हर साल गर्मी की दस्तक पर घटते भूजल स्तर पर विलाप तो होता है पर ज्यों ही मानसून आता है तो बेशकीमती पानी नालों में बेकार बहता है।

ऐसी कई जगह हैं, जहां पिछले 2 साल में 25-30 फीट तक भूजल नीचे चला गया है। फरवरी में ही बांध सूख रहे हैं। कोरे विलाप से प्यास बुझाने के भी लाले पड़ेंगे। एक ओर ग्लोबल वॉर्मिंग से तापमान बढ़ा है, वाष्पीकरण तेज हुआ है। मृदा से नमी खत्म हो रही है और खेती में पानी की मांग बढ़ी है। वहीं, शहरी जीवनशैली में ज्यादा उपभोग और बेतरतीब शहरीकरण के कारण यह समस्या और भयावह हुई है।

आमजन बने पानी का मालिक...

सरकारों ने बहा रखी हैं उलटी गंगा

अतुल चौरसिया

मैगसेसे पुरस्कार विजेता **राजेंद्र सिंह** का कहना है कि आमजन को पानी सहेजने का हक मिले। सरकारी नीतियां कारगर साबित नहीं हो पा रही हैं। प्रस्तुत है उनसे बातचीत के अंश.

Q ***लातूर के मद्देनजर क्या हम जल युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं?***

लातूर-उस्मानाबाद के हालात और दीर्घकालिक नीति बने। इन स्रोतों को सहेजने का कोई स्थायी उपाय नहीं है। कर्नाटक, तेलंगाना व बुंदेलखंड

विकेंद्रित सामुदायिक जल प्रबंधन वर्तमान जल संकट का हल है। पानी का अधिकार किसी उद्योगपति को देने की बजाय लोगों को पानी का मालिक बनाना होगा।

पानी का निजीकरण व व्यावसायीकरण कर सरकारों ने इस समस्या की नींव रखी थी। सरकार का नेट मुनाफा सबसे ज्यादा है। प्यासे आदमी और प्यासी धरती के पास पानी नहीं है। यह उलटी गंगा सरकारों ने बहा रखी है। कोकाकोला को लाइसेंस मिल जाता है, किसान को कुएं-ट्यूबवेल के लिए मंजूरी नहीं दी जाती।

Q ***शहरी-ग्रामीण जलस्रोत या तो प्रदूषित हैं या कमी का शिकार हैं। इसका कारण क्या है?***

आज बड़े शहरों को 100-150

बोतलबंद पानी का बढ़ता बाजार

हमारे पानी से वो कमाएं 160 अरब

संडे जैकेट डेस्क

शहरी इलाकों में 1990 के बाद पेयजल के मामले में पाइपलाइन के पानी पर निर्भरता में कमी आई। परिशुद्ध (ट्रीटेड) पानी का चलन बढ़ा। शहरी क्षेत्रों में बोतलबंद पानी को बेहतर स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाने लगा। ऐसे में पानी के कारोबार के निजीकरण का रास्ता खुल गया। पानी का कॉरपोरेटीकरण तेजी से बढ़ रहा है।

तीसरी दुनिया के देशों पर पानी के निजीकरण का दबाव बनाने के लिए आईएमएफ व विश्व बैंक ने इस शर्त पर कर्ज दिया कि उन्हें संसाधनों पर सरकारी नियंत्रण कम करना होगा।

लगभग 22 फीसदी है। पानी का कारोबार लागत और मुनाफे के लिहाज से बेहद आकर्षक है। लागत

अंधाधुंध तरीके से भूमिगत जल का दोहन करती हैं। अस्पष्ट सरकारी नीतियों के अभाव में बहुराष्ट्रीय

बोतल में बंद अर्थशास्त्र

बोतलबंद पानी के कारोबार की कहानी सिर्फ भारत से जुड़ा मामला नहीं है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलावों से जुड़ा मसला है। एक ओर जहां भारत में वर्ष 1990 में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने पहली बार बोतलबंद पानी को बाजार में उतार बड़े पैमाने पर विज्ञापन चला इसे सुरक्षित पानी घोषित किया।

ज्यादा गंभीर है। जब धारा 144 लगी मैं वहीं था। युद्ध जैसी स्थिति थी। समस्या अदूरदर्शी नेतृत्व की है। निवारण पर हमारी सोच शून्य है। सतही-भूमिगत जल भंडारण की

जैसे तमाम परतें, रेतीले इलाकों में पानी की विकट समस्या है।

Q *सरकार के अलावा जलसंकट की प्रमुख वजहें कौन सी हैं?*

ठेकेदारी प्रथा के भरोसे चल रहा है। एक कृत्रिम व्यवस्था बनाकर पानी जैसी प्राकृतिक जरूरत को सुलझाने का सपना देखा जा रहा है। देश में पानी का धंधा करने वाली कंपनियों

किमी दूर से पेजयल पहुंचाया जाता है। यह व्यावहारिक नहीं। गांवों के भूगर्भीय और सतही जल को सरकारें शहरों को भेज देती हैं।

पढ़ें सरकारों ने...@ पेज 05

वर्ष 2013 में देश में बोतलबंद पानी का बाजार 60 अरब रुपए का रहा। अनुमान है कि वर्ष 2018 तक यह 160 अरब रुपए का हो जाएगा। इस कारोबार की सालाना वृद्धि दर

मामूली होने की वजह से कंपनियों को जबरदस्त मुनाफा होता है लेकिन उसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ता है। कंपनियां पर्यावरणीय नियमों को ताक पर रख

कंपनियां पानी के रूप में एक ऐसे प्राकृतिक संसाधन को बेतहाशा निचोड़ रही हैं जिसकी मात्रा सीमित है, और जिस पर पहला अधिकार देश के नागरिकों का है।

दूसरी ओर 1992 में डब्लिन कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर एंड एनवायरमेंट में विकासशील देशों में पानी के निजीकरण की बुनियाद रखी गई।

पढ़ें हमारे...@ पेज 05

अब पढ़े संडे जैकेट ऑनलाइन कभी भी, कहीं भी patrika.com पर

नेशनल क्रिएटिव टीम

The Times of India
Title : `Don't forfeit Yamuna funds'
Author :
Location :
New Delhi:
Article Date : 04/02/2016

The NGT on Friday directed the DJB not to surrender the funds allocated to it for rejuvenation of the Yamuna in the last fiscal year to the Delhi government.The green panel also made it clear that DJB would spend these funds for restoration and the implementation of its `Maili se Nirmal Yamuna Revitalisation Project'.

The order was passed after the counsel appearing for the DJB expressed an apprehension that since the new fiscal year has started, the funds available with it will have to be surrendered. The counsel said that the DJB would be devoid of funds while contractors have to be paid for the work they have already done.

The NGT had earlier ordered the DJB not to spend a “penny“ on Yamuna rejuvenation without its approval.

The Times of India
Title : Above normal monsoon this year: Pvt forecaster
Author : Amit Bhattacharya
Location :
New Delhi:
Article Date : 04/02/2016

In the first forecast by any agency for this year's monsoon, a private company has predicted above normal and well-distributed rainfall in the country during the crucial June-September season.

Foraying into the tricky field of monsoon forecasting, Weather Risk Management Services, a risk management company that also provides meteorological services, released its long range prediction for the rainy season on Friday .It said rainfall is expected to be above normal, roughly more than 104% in most parts of the country , except the northeast.

The company also released percentage-wise forecasts for each month of the monsoon season as well as for each region, but said there was low confidence on these numbers at this stage. “At the moment, we are not highlighting specific numbers but just the general direction of the forecast,“ said Kanti Prasad, climate scientist at WRMS.

According to the forecast, all four months of the monsoon season are likely to get above normal rains countrywide, with June having the highest positive departure from normal and September the lowest. June rainfall is likely to be highest from normal in south, central and northeastern regions, while in northwest India, July , August and September are expected to be wetter than normal, it said.

The prediction should bring hope for farmers and the agriculture sector, battered by consecutive monsoon failures in the past two years. In 2014-15, agriculture showed negative growth of -0.25%, and grew at a modest 1.2% in 2015-16.

The company said it mainly based its forecast on results from the dynamical climate model used by US government's weather agency , NOAA, which are in the public domain.

The biggest factor favouring good rainfall, WRMS said, was the projected weakening of El Nino conditions. “Most ENSO prediction models indicate continued weakening of El Nino conditions over the coming several months, returning to neutral by late spring or early summer 2016, and a chance of La Nina development by fall,“ its release said.

WRMS is the second Indian private company to make public forecasts on the monsoon. Private forecaster Skymet has been predicting the monsoon for a few years now.Both companies rely on data from computer models of international weather agencies, in contrast to the India Meteorological Department which generates its own data.

HOPES HIGH?

The Times of India
Title : Asia faces severe water crisis by '50
Author :
Location :
Washington:
Article Date : 04/02/2016

Rising Economic Activity, Population Boom & Climate Change To Blame: MIT

Countries in Asia, including India, may face severe water shortage by 2050 due to rising economic activity , growing populations and climate change, MIT scientists have warned. There is a “high risk of severe water stress“ in much of an area that is home to roughly half the world's population, scientists said.

Having run a large number of simulations of future scenarios, the researchers found that the median amounts of projected growth and climate change in the next 35 years in Asia would lead to about 1 billion more people becoming “water-stressed“ compared to today .

While climate change is expected to have serious effects on the water supply in many parts of the world, the study underscores the extent to which industrial expansion and population growth may by themselves exacerbate water-access problems.

“It's not just a climate change issue,“ said Adam Schlosser, from the Massachusetts Institute of Technology (MIT) in US.

“We simply cannot ignore that economic and population growth in society can have a very strong influence on our demand for resources and how we manage them.And climate, on top of that, can lead to substantial magnifications to those stresses,“ said Schlosser.

To conduct the study , the scientists built upon an existing model developed previously at MIT, the Integrated Global Systems Model (IGSM), which con tains probabilistic projections of population growth, economic expansion, climate, and carbon emissions from human activity .

They then linked the IGSM model to detailed models of water use for a large portion of Asia encompassing China, India, and many smaller nations.

The scientists then ran an ex tensive series of repeated projections using varying conditions. In what they call the “Just Growth“ scenario, they held climate conditions constant and evaluated the effects of economic and population growth on the water supply .In an alternate “Just Climate“ scenario, scientists held growth constant and evaluated climatechange effects alone.

And in a “Climate and Growth“ scenario, they studied the impact of rising economic activity, growing populations, and climate change. Approaching it this way gave the researchers a “unique ability to tease out the human (economic) and environmental“ factors leading to water shortages and to assess their relative significance, Schlosser said.

'A time like Emergency won't come again... Cases happen, but BJP never starts them'

Uma Bharti, Minister for Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, claims Sri Sri event left Yamuna floodplains cleaner, says Centre is planning a law to restrict fresh water use, asserts India is the "safest place for minorities" and says while BJP faith may be Hindutva, its agenda is development

Uma Bharti with Senior Editor Shyamlal Yadav at *The Indian Express* office. *Renuka Puri*

SHYAMLAL YADAV: When the government was being formed at the Centre, you were considered a natural claimant to the Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation Ministry.

I was considered a natural claimant to the Ministry not just because of my work on the Ganga river, but with water in general. Water management, water resources... I am very attached to water, I am not scared of it.

When I was given the Water Resources Ministry, I was extremely pleased. I knew that until now the ministry was only concerned with releasing grants, it did not really have a role of its own. There were no independent proposals from the ministry.

For the Ganga, I had thought things through in a very comprehensive manner. I met everyone attached with the river. We discussed things from a scientific and environmental point of view. We also spoke to people who are economically dependent on the river and even those who have suffered because of it.

SHYAMLAL YADAV: There have been attempts to clean the Ganga since 1985, but without much success. Do you think it is possible to achieve a Biochemical Oxygen Demand of less than 2 and Dissolved Oxygen of more than 6 mg/litre — i.e. water that can be used for drinking without any treatment — in the Ganga water?

See, even if mineral water from a commercial brand is checked in an international lab, there are bound to be problems in it. The labs may say that this water is not good for your health. So, Ganga water cannot be examined under such a criterion. Right now, Ganga is considered to be one of the ten dirtiest rivers in the world. But if we manage to get the river enlisted among the cleanest rivers, then we will truly achieve our target. Personally, I think the proof of Ganga's cleanliness will come from its aquatic life. If Ganga is cleaned, then the aquatic life that thrived in the region will return — the turtles, dolphins, goldfish. Right now, there is none of it.

So now we have created a programme around this (aquatic life). We will now check the Ganga from the point of view of the creatures which inhabit the river.

SHEELA BHATT: Since the BJP government came to power at the Centre, you seem to be maintaining a low profile, especially in the politics of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh.

This is the happiest time of my life. Since I joined the party, I wanted the BJP to get a majority at the Centre, like it has now. Secondly, before the 2014 general elections, the impression that many people in the country had about the party was that we only do *bhajan* and *kirtan*. But we managed to break that perception by showing that we were pro-development.

Our faith is in Hindutva, but the agenda for governance is development, and there we don't differentiate on the basis of caste and religion. In the earlier years, our victory was limited to states — Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Gujarat. But after the 2014 general elections, I was satisfied on two accounts — first that the BJP got a majority, and secondly, that we achieved success on the agenda of development.

On top of this, I was given the water resources portfolio. So this is the most beautiful time of my life, and I want to enjoy this as I work. I don't care if I am in the news or not.

COOMI KAPOOR: Did you agree with the permission given to Sri Sri Ravi Shankar to hold the World Culture Festival on the Yamuna floodplains?

Technically speaking, it was not the job of my ministry to grant permission for the event. That comes under the Environment Ministry. There was some confusion initially, but I had immediately clarified.

Actually, the venue where the programme was held was a very dirty place, and in fact it has now become cleaner. Pigs, buffaloes, scorpions and snakes used to roam there. With Sri Sri Ravi Shankar's event, Yamuna river was highlighted and the area was made better, cleaner.

SHEELA BHATT: There has been no decision on the chief ministerial candidate for Uttar Pradesh yet by the BJP, but you seem to be one of the probables. How do you see the political situation in the state and what would be your role in the elections?

The decision on who should be the CM candidate and who shouldn't be depends on the Centre and the state. For now, my only role in UP will be that when I am asked, I will go there. Apart from this. I don't think about my role in the state.

In a state, the local BJP leaders and workers have specific roles. These people need to think about their strategy. Why did they lose in Bihar? How will they win in Assam? How will they win in UP? The BJP leaders, workers have to plan. People like me will help anywhere, wherever Amit Shah asks, we will help.

AMITABH SINHA: The government has set up a panel under Professor K S Valdiya on the Saraswati river. If the panel says that such a river does exist, is there a model on which you plan to base the efforts of reviving the river?

We have heard of dirty rivers being cleaned, like the Thames in London, but stories of revival of old rivers haven't come to the fore yet. I think the problem (of rivers drying up) is mostly limited to the Indian subcontinent. Australia has fixed its river basin. In India, we have let water dry up and didn't care. We used up both the surface water and ground water. This problem can arise in Pakistan and Sri Lanka too. We should really look for these dried-up rivers, and we have made a task force for this purpose. B N Navalawala who was Modiji's advisor for 10 years is now our chief advisor. Under his chairmanship, there is a task force that is examining India's dry areas to see if there are dried-up streams of water.

These streams cannot be revived immediately. But if rainwater is collected in these zones, trees are planted, water will eventually seep through the soil and these streams will get recharged. The water table in the surrounding areas too will start rising.

See for now, there is no evidence of the Saraswati in the *Triveni*, we just have the Ganga and Yamuna. (Saraswati is considered an invisible part of the confluence in Allahabad). Research is underway. For now, we cannot call it (the dried-up stream) the Saraswati river. We will get the water tested and the team will then decide what needs to be done.

I have told him (the head of the Saraswati committee, Prof K S Valdiya) that only after proper research will we announce the presence of the Saraswati river. We believe it is the Saraswati, but we need proof. So we have requested that the panel should have sittings in Bengaluru itself, as Valdiya*ji* cannot travel. The team give him all the proof and we will accept the results.

AMITABH SINHA: What are the experts telling you now? Will we be able to see a river and can it be used to recharge the water table?

It is believed that the river Saraswati was pushed down because of an earthquake. In some cases, because of an earthquake, rivers are known to come to the fore too. In Madhya Pradesh, there was an earthquake in the '90s. My village is 250 km from Jabalpur. After the earthquake, the water in the well of our village rose, and for almost two years, the water table stayed up.

See, I don't think that there is a stream flowing underground (in case of Saraswati), but I do believe that the water must be mixed with sand, there must be some moistness in the soil. For our efforts to be successful, the society will have to participate so that the water table in the region can be recharged. Here the MGNREGA will be important too. Species of trees that will help in recharging the ground water will have to be planted.

MANEESH CHHIBBER: Since your government came to power, there have been many controversial statements by your leaders. These diverge from the development agenda that the Prime Minister talked about at the start of his government.

People working in the government have never drifted from the development agenda. Those making the controversial statements are not in the government, at least most of them are not. The controversial comments are highlighted in news, but the work of the government is also going on. The road, water and electricity work is on track.

Whatever has happened till now, like the Rohith Vemula, Kanhaiya Kumar cases, it is in fact Rahul Gandhi who has suffered the most because of them. Whatever little votes he got, the ones that didn't go to Mulayam Singh Yadav, Mamata Banerjee or Lalu Prasad, he has lost even those now. So if anything, these events are a bigger concern for Rahul Gandhi.

MUZAMIL JALEEL: In the last two years, with incidents like Dadri etc., there seems to be an increase in social tension in the country. It seems that people who are within the government and those outside it are working on two different briefs.

Firstly, there have been social tensions all over the world. Europe's perspective has changed. Donald Trump (front-runner for the Republican nomination in the US presidential race) has also started getting many followers in America.

India is the safest place for minorities. It is the most tolerant country because we have faced a big tragedy like the Partition. I find it absurd when people like Rahul Gandhi raise questions because he seems to have forgotten that the Emergency was declared in the country during the Congress regime, and lakhs of Muslims were castrated, they were forced to do family planning. Many died during surgery itself. Lakhs of innocent people were put in jails. The Congress party has absolutely no right to talk about freedom of expression. The biggest victims of the Emergency were the minorities.

Now, that time has passed and a phase as bad as that has never come again in the country and we will not let it come. I give this guarantee. Yes, if some small incidents happen, then people will react and speak, but we (the BJP) never start any of it. Dadri did not happen in our state. We don't have a government in Uttar Pradesh.

Wherever we are in power and an untoward incident occurs, action is immediately taken, like in Haryana (after the Jat quota protests).

Where do Naxalites and Maoists come from? They are people with extreme interpretations of socialist and Communist movements. But you cannot blame all socialists and Communists for their actions.

The best thing about India is elections. There is democracy in our country and people reject things that they don't like. In five years, things change.

SHYAMLAL YADAV: On many occasions, you have mentioned that you will not allow hydropower projects on the banks of the Ganga. Now an affidavit has been filed in the Environment Ministry seeking clearance for three projects. You did not agree with the move. You also wanted powers under Section 5 of the Environment Protection Act. Have you raised these issues with the PM?

See, I have never opposed hydropower projects. I simply said that for any project, regarding irrigation or power, the river should not be destroyed. Rivers cannot be remade, they are natural entities.

What I said was that the world has progressed so much, such high-level technology is available to us, so we should come up with a design in which at least one stream of the river must keep flowing. We call it ecological flow or e-flow. The concept of e-flow in India has been introduced by my ministry and I have put a lot of emphasis on it. I have told the Central Water Commission (CWC) that whenever a dam is designed, there should be an e-flow assessment. Don't design a dam on the river, make it on the side of the river, so that monsoon water can be captured and the river bed stays unharmed.

So yes, I have propagated the e-flow concept and a few hydropower projects can get into trouble because of this. But if these projects are willing to rework their design, it will be fine.

Last year on March 25 there was a meeting which the PM attended, where we asked for Section 5 powers (closure, prohibition or regulation of any industry, operation or process by the Centre), because when we are the NGRBA (National Ganga River Basin Authority), we should be given the power to take action against all sources of pollution concerning the Ganga. Right now we only have the power of recommendation. The power to take action is with the Central Pollution Control Board (CPCB). But our demand was opposed by both the Environment and Law Ministry.

After I raised the issue, the Prime Minister made a high-level task force under the Cabinet Secretary and said that whichever industry is polluting the river, strict action should be taken against them.

AMITABH SINHA: A number of private parties are now involved in the functioning of Sewage Treatment Plants (STPs). Are we heading towards a future where treated water made at these plants will have to be bought?

In case of the Ganga, we have decided that the treated water must not be allowed to flow into the river. So where will this treated water go? Efforts will have to be made to create a market for treated water. Farmers can buy it for irrigation and gardening. We are aware that some treated water might not be suitable for irrigation, like that coming out as effluent from certain industries. So those industries will have to recycle their water.

Fresh water, whether it is surface water, ground water or reserved rain water, cannot be used for every purpose. We would have to bring clarity on the uses it can be put to and the purposes it cannot be used for. Otherwise, we are staring at a huge water problem in the country.

Under the Constitution, water is a subject to be dealt with by the state governments. But, if needed, we can bring in a law. A draft is already being worked upon. We will take the concurrence of the state governments on the uses of fresh water. It cannot be used for everything. We need to conserve water.

COOMI KAPOOR: In your political career so far, what has been your biggest regret — stepping down from the post of CM in Madhya Pradesh or when you left the BJP at one stage?

I have never said that I want to be the CM of Madhya Pradesh again. I have just said that I should be consulted about who gets the post. Right now, I just want to forget the whole incident (stepping down from MP CM post in 2004). I have always worked with emotion and conviction, and there has been no room for regret.

But I have to say that it is only now that I am happy being a politician. Earlier I used to regret being in the profession. But ever since I was given the Water Resources Ministry, I have been happy. Maybe this has been my life's purpose. Ultimately, I feel, Narendra Modi has converted my life's regret into a success. But yes, I have never been a politician.

Transcribed by Somya Lakhani, Pooja Khati & Pallavi Pundir

WHY UMA BHARTI

Uma Bharti has been the chief minister of Madhya Pradesh and also served as a Union minister in Atal Bihari Vajpayee's Cabinet. A prominent leader of the Ramjanmabhoomi movement who was known for her fiery speeches in the late '80s, Bharti is among the few saffron-robed leaders to find a place in the Modi Cabinet. She has been given charge of Water Resources, River Development, Ganga Rejuvenation Ministry in a government that has called cleaning the Ganga river a mission, and set up a panel on the mythical Saraswati

> "Where do Naxalites and Maoists come from? They are people with extreme interpretations of socialist and Communist movements. But you cannot blame all socialists and Communists for their actions... The best thing about India is elections. There is democracy in our country and people reject things that they don't like. In five years, things change"

THE HINDU

» TODAY'S PAPER » NATIONAL

Published: April 3, 2016 00:00 IST | Updated: April 3, 2016 05:43 IST NEW DELHI, April 3, 2016

Centre plans model law on groundwater

- Jacob Koshy

Ministry likely to start consultations with the States

The Central government is likely to begin consultations with the States to frame a Bill to prevent the misuse of groundwater, a rapidly diminishing resource in India.

"Water is a State subject and it is incumbent on States to protect their resources ... we will consider a model Bill to help with this," says Union Minister for Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation Uma Bharti.

Experts from the Union Water Resources Ministry have visited a few States to ascertain the groundwater situation, Shashi Shekhar, Secretary, Water Resources, says.

Mr. Shekhar, however, cautioned that it was too early to moot penalties and firm targets for those States that had failed to check water misuse.

All groundwater is considered freshwater, which, however, can also include water from ponds, lakes and other sources of surface water.

The management of water is a State subject in India and that has complicated efforts to manage water resources. The India Water Week — a multidisciplinary conference, set to begin on Monday, to discuss India's challenges with freshwater management — will have a session on legal remedies to address the depleting groundwater resources and also discuss legal aspects of the issue, Ms. Bharti says.

The India Water Portal says as much as 85 per cent of drinking water in rural area is drawn from wells, with 88 per cent of it used for irrigation.

Up to 48 per cent of the urban population uses groundwater.

A recent study by the Central Ground Water Board found that groundwater exploitation and contamination has affected nearly 60 per cent of Indian districts.

This is not the first time that the Centre has mooted legislation for the management of groundwater.

Since the 1970s, says a report by the now-renamed Planning Commission, laws have been mooted to encourage States to use groundwater more judiciously but except for Andhra Pradesh, Bihar, Goa, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Maharashtra (drinking water focus), Tamil Nadu, West Bengal and union territories such as Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Lakshadweep and Pondicherry, these laws haven't been effectively implemented.

Central experts have already

visited a few

States to ascertain the situation

Printable version | Apr 4, 2016 4:33:48 PM | http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/centre-plans-model-law-on-groundwater/article8427713.ece

© The Hindu

Three weeks after Yamuna fest, clean-up far from over

WORK IN PROGRESS Though most parts are clean, plastic waste dots the area

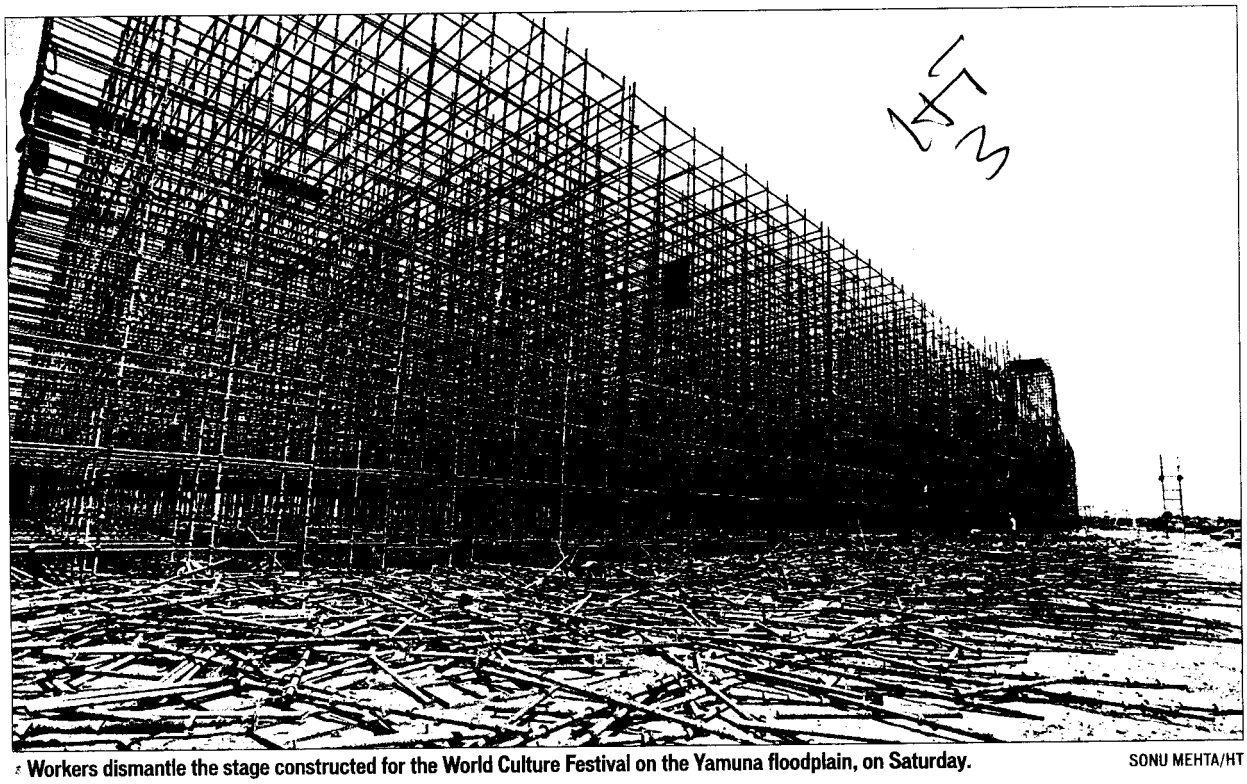

Workers dismantle the stage constructed for the World Culture Festival on the Yamuna floodplain, on Saturday. SONU MEHTA/HT

Ritam Halder
ritam.halder@hindustantimes.com

NEW DELHI: Three weeks after the World Culture Festival event was held on the Yamuna floodplain, the clean up work at the venue is in progress and will take more time to complete.

Hindustan Times on Saturday visited the site to assess the progress of the clean-up. Labourers at the site said it would take another month to dismantle the seven-acre stage.

"Three groups of workers belonging to different contractors are dismantling the stage. It is a labour-intensive job and will take time," said Raju (name changed on request).

Giant cranes, trucks and nearly 100 men were seen in action. A few security guards were also deployed at various corners of the site. "Apart from the stage, all other structures have been dismantled," said one of the guards.

Even though most parts of the site have been cleaned, plastic waste dot the area. When rain played spoilsport on the opening day of the festival on March 11, plastic sheets were placed around the stage to keep the muck away. These have now become part of the soil at many places.

A spokesperson for the Art of Living said the clean-up would be complete once the stage was removed.

The event that took place from March 11 to 13 saw lakhs of spiritual leader Sri Sri Ravishankar's followers converge at the site. The event was under the scanner for causing damage to the floodplain. The National Green Tribunal had allowed the Art of Living Foundation to hold the event on the condition that it paid "restoration costs" for damaging the environment. It imposed an initial cost of ₹5 crore on the foundation.

Plastic waste and debris around the seven-acre stage. RITAM HALDER

> **Three groups of workers belonging to different contractors are dismantling the stage. It is a labour-intensive job and will take time.**
>
> A LABOURER AT THE VENUE

Subsequently, the court said, the foundation would have to pay restoration costs for damage caused to the environment, ecology, biodiversity and aquatic life. The cost will be decided by a committee appointed by the court.

The event stirred another controversy when the government told the army to build two floating bridges on floodplain for the event.

The government had come under Opposition criticism in Rajya Sabha.

Several serving and retired officers said the army should not be involved in providing equipment and soldiers for private events as it was a strain on its resources and dented its image.

Operation should be over by mid April, says AoL

NEW DELHI: The clean-up operation of the mega Art of Living event, under the scanner for damage to the fragile floodplain of the Yamuna, is expected to be over by mid-April.

Rashmi Palliwal, one of the organisers of the three-day World Culture Festival, said even though most of the cleaning is done, dismantling the huge stage will take time.

"Most of the ground has been cleaned up. The seven-acre stage area is left and we expect it to be over by the middle of April," said Palliwal, also a trustee of the Art Of Living Foundation

According to her, agencies and volunteers helped in the clean-up after the festival ended on March 13. Over 400 volunteers helped in cleaning during the event. After the event, many volunteers still kept visiting the site everyday for cleaning, she said.

The Municipal Corporation of Delhi and Delhi Jal Board also helped, she said.

"Our role is to make the site the way it was. We have taken on board a few environment experts. One of them is Dr Rakesh Ranjan, who is an environmental consultant... However, we won't allow any damage to the environment," Palliwal said. **RITAM HALDER**

and documentation (English) & Publicity Section, CWC

FARMERS' PLIGHT

MSP failed as security blanket for farmers: Panel

REVIEW Two government reports have suggested an overhaul of the mechanism to fix grain prices to make it 'realistic' for farmers

Chetan Chauhan
chetan@hindustantimes.com

NEW DELHI: Two government reports have suggested an overhaul of the mechanism to fix grain prices to make it "realistic" for farmers at a time when agriculture income growth has slumped to its lowest in recent years.

Back to back drought and unseasonal rainfall in two consecutive springs have farmers struggling, with farm income slated to grow at less than 3% in 2015-16 as against 15% the previous year.

Farm wages, a source of income for about 62% of the rural population, too were affected, and recorded almost negligible growth, according to a report of the ministry of statistics and programme implementation.

Among other reasons, the effect of adverse weather conditions was compounded by a faulty price determination policy called minimum support price (MSP), found a report of the National Institution for Transforming India.

MSP is a tool that guarantees to farmers, prior to the sowing season, a fair fixed price for their crop to encourage higher investment and production.

However, many states such as Assam, Rajasthan and Uttar Pradesh failed to announce the MSP before the sowing season, and when they did, it was grossly inadequate. In fact, it was lower than the cost of production.

For instance, the 2014-15 MSP for sunflower was ₹4,700 per quintal whereas the actual agricultural cost was ₹5,189. Similarly, for ragi, the difference between its MSP and the production cost was about 20%, forcing farmers to opt for an alternate crop.

"The MSP scheme requires a complete overhaul in states where the impact of the scheme ranges from 'nil' to 'at-best marginal' to ensure that MSP as an important instrument of the government's agricultural price policy is not undermined," said the NITI Aayog report based on a survey in 14 states.

A National Sample Survey Office (NSSO) survey report released in December last year found half the farmers who sell their produce in the market were unaware of MSP. It also pointed out that many did not have even the option to sell at MSP in the absence of a nearby "procurement agency".

Around one-fourth of about 35,200 farming households surveyed in 2012 said the MSP was of no utility as it was not realistic.

THE PRESSURE OF DEBT

Mounting loans due to successive droughts, hailstorms and insufficient rain have forced many farmers to commit suicide

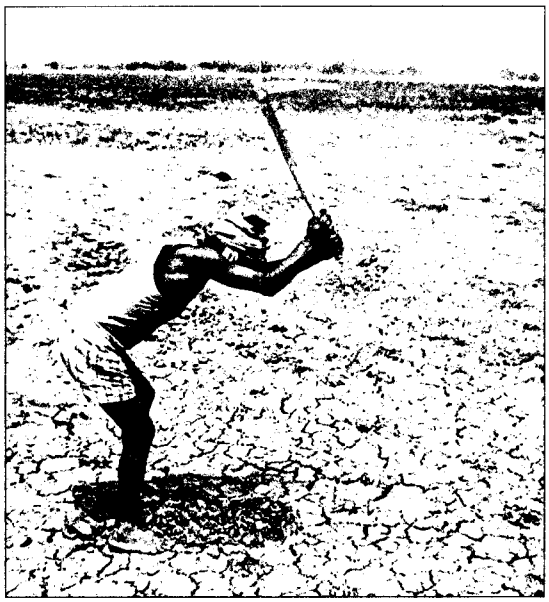

One-fourth of about 35,200 farming households surveyed in 2012 said the minimum support price was of no use. HT FILE

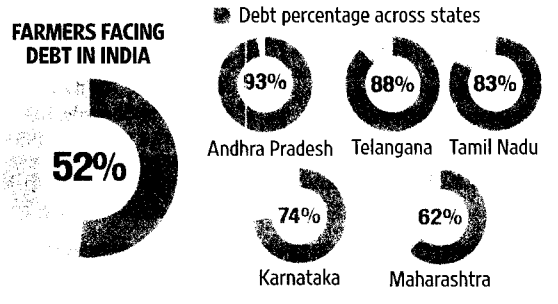

SOURCE: NSSO SURVEY DECEMBER 2015

Hailstorm in Bundelkhand destroys homes, dreams

INSUFFICIENT RAIN DASHED HOPES

Rainfall across districts of Bundelkhand in Madhya Pradesh in 2015

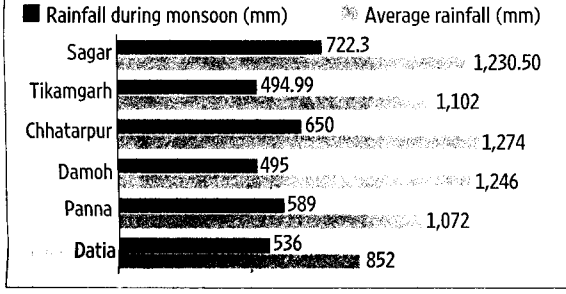

Rahul Noronha
rahul.noronha@hindustantimes.com

JATARA (TIKAMGARH): The dilapidated mud houses of Tikamgarh district's Harpura village could easily be mistaken for a town in a war-torn country. But it wasn't bullets and bombs that wreaked havoc in this farming village.

A massive hailstorm on March 14 not only destroyed their homes, but also their dreams of recouping from a dismal kharif season — their ready-to-harvest crop was virtually obliterated.

"This crop was the only hope," said Jairam Singh Ghosh, 55, who took a loan to sow wheat after his soybean crop wilted away because of a deficient monsoon. "I have borrowed money to buy seed and fertiliser, but don't know how it will be repaid."

At least half the houses now lie empty as many were forced to leave in search of work. "I have no option but to migrate," Ghosh said.

The chief minister visited Harpura two days later and announced a compensation of ₹15,000 per hectare, just as the state did for the kharif crop. But, when land is held jointly by families and fragmented, individuals who were lucky to be paid received as little as ₹1,500.

About 30% farmers in Jatara are yet to receive the amount.

Another failure of a government scheme was pointed out by Babu Rajak of Berwada, a small settlement on the Jatara-Lidhora Road. He said a majority of farmers still do not have a "kisan credit card" for crop insurance.

Helpless, many farmers decided to end their lives.

Mercury soars to 39°C, rain likely in parts of city today

Boys beat the heat on a sunny Saturday in the national capital. SONU MEHTA/HT

Press Trust of India
htreporters@hindustantimes.com

NEW DELHI: It was a hot day in the national capital on Saturday with the maximum temperature settling at 38.9 degrees Celsius, five notches above the normal.

The minimum temperature was recorded at 21.5 degrees Celsius, three notches above the season's average, a Met department official said.

The humidity level in the air oscillated between 23% and 74%, though the weather in the morning was rather pleasant with 60% humidity.

THE MET DEPARTMENT FORECAST A MISTY DAY FOR TODAY, RAIN AND THUNDERSHOWERS LIKELY IN THE EVENING AND NIGHT

The weatherman forecast partly overcast conditions along with possibility of rain for Sunday.

"The skies will be partly cloudy. Rain and thundershower are likely to occur in some parts of Delhi and NCR towards the evening and night tomorrow. Mist or haze may occur in the morning. The maximum and minimum temperatures are expected to hover around 40 and 22 degrees Celsius respectively," he said.

Friday's maximum temperature settled at 37.3 degrees Celsius, four notches above the season's average, while the minimum temperature was recorded at 21.6 degrees Celsius, three notches above the season's average.

Delhi goes above 40°C weeks before time

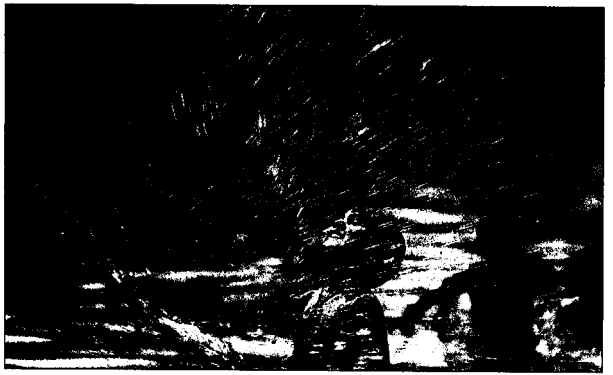

■ Children beat the heat with a dip in the pond at India Gate on Sunday. At least three places in the city breached the 40-degree mark. RAJ K RAJ / HT

HT Correspondent
■ letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The heat is on. Delhi on Sunday got a taste of the harsh summer to come with the Palam weather station recording a maximum temperature of 43 degree Celsius — highest in the first fortnight of April in 47 years.

Two other places — Ayanagar in southeast and Jafarpur in southwest Delhi — also breached the 40-degree mark, recording 40.6°C and 40.1°C, respectively.

"It is very unusual for this time of the year. Even between April 16 and April 20, there have been only two instances in 47 years —1984 and 2010 — when the maximum at Palam touched 43 degrees," said RK Jenamani, director in-charge of the weather office at IGI airport.

The Safdarjung station, which records the official readings for Delhi and is usually cooler than Palam, reported a maximum temperature of 39.4 degrees and minimum of 24.8 degrees, both six notches above normal.

According to the Met department, Monday might provide some respite from the heat with light thundershowers in the morning. The temperature is expected to be between 23 and 38°C.

Is the mighty Ganga drying up?

Last month, the NTPC plant near Farakka barrage was shut down after flow dipped

VIDYA VENKAT

CHENNAI: The Ganga that has nourished the Indian civilisation for centuries has recorded a historically low inflow in its lower reaches this year, going by the evidence on the ground. The inflow at the Farakka barrage in West Bengal nearly halved, compared with the quantum of water available in the last two years. The NTPC's plant beside the barrage had to shut operations from March 10.

Though statistical information on the inflow is not in the public domain, because the river is an international resource, protected for strategic purposes, *The Hindu* obtained local water level data to verify claims of a reduced inflow. A.K. Pal, superintending engineer at the Farakka barrage, confirmed: "On March 29, the inflow discharge observed in the Ganga by the India-Bangladesh joint observation team was 50,710 cusecs, while in comparison the discharge on 29/03/2014 and 29/03/2015 were 91,001 cusecs and 83,807 cusecs respectively."

HISTORIC LOW: The inflow at Farakka barrage nearly halved, compared with the water available in the last two years.

Himanshu Thakkar, coordinator of the South Asia Network on Dams, Rivers and People, said this was a scary development with the summer just beginning. "We are already seeing a historically low inflow downstream of the Farakka in the Ganga, which reflects the health of the entire river basin," he said. He blamed the situation not only on deficit rainfall and a dry winter but also on the increasing exploitation of the river in its upper reaches.

West Bengal Pollution Control Board chairman Kalyan Rudra, considered an authority on the river, ruled out greater quantum of water being diverted to Bangladesh, under the international water sharing treaty, as the cause for the reduced levels.

■ CONTINUED ON PAGE 12

FROM PAGE ONE

Is the mighty Ganga drying up?

"While this is the initial understanding, the reasons could be more varied. In the upper catchments, the first intersection of water happens in the hydel power projects, then once the river reaches near Haridwar, there is withdrawal for irrigation. From hereon, there is considerable exploitation of groundwater for irrigation, which affects the base flow. Indiscriminate withdrawal might be one of the causes. Though the Ganga goes dry during the lean season from March, historically low inflow underscores serious concerns over upstream withdrawal," he said.

Glaciologists studying the Himalayan sources of the river allay concerns that reduced snowmelt from the retreating glaciers might further affect the water levels, though they are divided over the extent of the impact. "That the glaciers are receding is true, but the Gangotri is not going to vanish," says Manohar Arora, scientist at the National Institute of Hydrology (NIH), Roorkee.

> Glaciers are receding, but the Gangotri is not going to vanish, says an expert

The glacial retreat has affected the flow but its effects have been more localised, according to NIH Director R.D. Singh. "...the amount of water coming from the glacial melt to the Ganga is not so significant as to affect the entire river basin. So we need to look at tributaries to the river coming from Nepal as 80 per cent of the river's flow downstream comes from there."

The coordinator of the Ganga River Basin Management Plan, Vinod Tare, also a professor at the IIT-Kanpur, said studies conducted by the IIT had shown that anthropogenic stress through expansion of cities by the river, denudation of forests, encroachment of floodplains and excess groundwater extraction had affected the river severely.

Deficient rain makes Vansda thirsty

HimansshuBhatt
@timesgroup.com

30 March TOI

Main source of water Kaveri River has almost dried up

Surat: Authorities have started supplying water through tankers in Vansda, the taluka headquarters in Navsari district, because it is in the midst of a crisis since a fortnight now. Vansda, which has a population of 16,000 and is located 90km from Surat city, received deficient rainfall in 2015, leading to drying up of its water sources. Kaveri River has almost dried up in Vansda, which otherwise records 1,800mm of rainfall in a year. The end result is Jaju dam with 27.58 MCM capacity built on Kaveri has been rendered almost useless, and at present is under repairs. Nearly 5,500 households in Vansda that used to be supplied 2,000 litre of water daily are getting just half the regular supply. The 2,000 households that don't have storage facility are being supplied water through tankers daily by the authorities.

Vasada Panchayat sarpanch Budha Patel said, "We were dependent on the dam for water. However, as it had developed leakage, irrigation department emptied out the water. Our town's filter plant is closed and borewells don't throw up water even at 110 feet."

D C Patel, deputy engineer, irrigation department, said, "Poor rain last monsoon has led to this situation. The water level in the dam could not go beyond 30 per cent of its storage capacity. The dam is under repairs currently."

Gujarat Water Supply & Sewerage Board dug a borewell at Vansda a few days ago. It would be digging two more borewells from April 1. Vasada panchayat member Ilyas Paraniya said, "Three tankers are providing water to Vansda, but it is not sufficient to meet people's needs."

District collector Remya Mohan said, "Water will be supplied to Vansda and a long-term plan drawn for underground water recharge and conservation in the taluka."

Above normal monsoon this year: Pvt forecaster

Amit.Bhattacharya
@timesgroup.com

New Delhi: In the first forecast by any agency for this year's monsoon, a private company has predicted above normal and well-distributed rainfall in the country during the crucial June-September season.

Foraying into the tricky field of monsoon forecasting, Weather Risk Management Services, a risk management company that also provides meteorological services, released its long range prediction for the rainy season on Friday. It said rainfall is expected to be above normal, roughly more than 104% in most parts of the country, except the northeast.

The company also released percentage-wise forecasts for each month of the monsoon season as well as for each region, but said there was low confidence on these numbers at this stage. "At the moment, we are not highlighting specific numbers but just the general direction of the forecast," said Kanti Prasad, climate scientist at WRMS.

HOPES HIGH?

According to the forecast, all four months of the monsoon season are likely to get above normal rains countrywide, with June having the highest positive departure from normal and September the lowest. June rainfall is likely to be highest from normal in south, central and northeastern regions, while in northwest India, July, August and September are expected to be wetter than normal, it said.

The prediction should bring hope for farmers and the agriculture sector, battered by consecutive monsoon failures in the past two years. In 2014-15, agriculture showed negative growth of -0.25%, and grew at a modest 1.2% in 2015-16.

The company said it mainly based its forecast on results from the dynamical climate model used by US government's weather agency, NOAA, which are in the public domain.

The biggest factor favouring good rainfall, WRMS said, was the projected weakening of El Nino conditions. "Most ENSO prediction models indicate continued weakening of El Nino conditions over the coming several months, returning to neutral by late spring or early summer 2016, and a chance of La Nina development by fall," its release said.

WRMS is the second Indian private company to make public forecasts on the monsoon. Private forecaster Skymet has been predicting the monsoon for a few years now. Both companies rely on data from computer models of international weather agencies, in contrast to the India Meteorological Department which generates its own data.

Publicity Section, CWC

Will learn water conservation from guru Israel: Uma Bharati

Vishwa.Mohan
@timesgroup.com

MAKING DO WITH LITTLE WATER: LESSONS FROM TEL AVIV

India has **18% of the world's population**, but it has only **4% of the world's water resources**

1869 billion cubic meters (BCM)
Average annual water availability

1,123 BCM
690 BCM Surface water
433 BCM Groundwater
Average annual potential of 'utilisable' quantity of water

ANNUAL PER CAPITA AVAILABILITY OF WATER

PROJECTION: Annual per capital availability of water will be reduced to **1,340 cubic metre** by 2025 (1 cubic metre = 1,000 litres)

(Source: Ministry of Water Resources; Embassy of Israel, New Delhi)

ISRAEL

- With a **85% water recycling rate**, country is world's number one water recycler (Spain with 12% water recycling rate is the 2nd largest water recycler)
- **Israeli-invented 'drip irrigation'** helps achieve 70%-80% of water efficiency in agriculture – the highest rate in the world
- **Israel has achieved the highest ratio** in the **world of crop yield per water unit**
- **Israel's total water consumption** has remained the same since the 1960s despite a growing population and rising water requirements

New Delhi: "We have to learn a lot from Israel...*hum Israel ko apna guru banayenge* (we'll make Israel our teacher) in the field of water conservation," said water resources minister Uma Bharati on Saturday while announcing the government's plan to observe 'India Water Week' from April 4 to 8, where Israel will be the country partner.

The idea of water week, which is being organised in the backdrop of an acute water crisis in Latur in Maharashtra, is to discuss all issues relating to water conservation and water use efficiency in domestic, agriculture and industrial sectors.

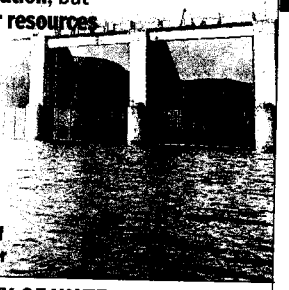

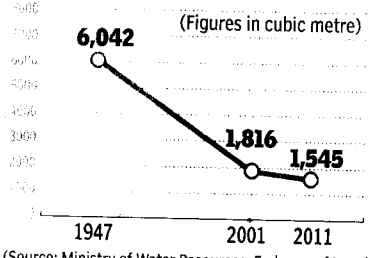

Referring to the crisis in Latur, one of the worst-hit districts in parched Marathwada, Bharati said that a fact-finding team from the central water commission would visit the place to study the severe water shortage in the region and find ways to tackle the problem. 'Israel which has long experience and expertise in managing its water resources can help us a lot", said Bharati.

Explaining how Israel could be a partner in promoting water conservation, Israel's ambassador to India Daniel Carmon said after defence and agriculture, water would be the next big collaboration between the two countries.

Israel's agriculture minister Uri Ariel will visit New Delhi to participate in the 'India Water Week' where the country will organise various exhibitions, showcasing technologies available for improving efficiencies.

Punjab, Haryana get central grant for potable water

4 April - T

MUKESH RANJAN
TRIBUNE NEWS SERVICE

NEW DELHI, APRIL 3
Faced with the problem of fluoride and arsenic material contaminating their potable water resources, 15 states are set to receive a special assistance from the Centre to tide over the crisis.

The government has already released ₹72,676 lakh for the states following an advice from NITI Aayog.

In the north, Punjab, Haryana, Rajasthan and Jammu & Kashmir figure on the list and would receive ₹3,935 lakh, ₹266 lakh, ₹43,129 lakh and ₹47 lakh, respectively.

A release order (The Tribune has a copy) issued by the Department of Expenditure, Ministry of Finance, said, "The amount for special assistance grant is being released on the examination and recommendation by NITI Aayog and the states need to follow certain conditions while utilising the fund."

The states would have to transfer the amount to implementing agencies within 15 days of its receipt from the Centre. "Any delay will require the state governments to release the grant with interest at prevalent RBI rate for the period of default," it said.

The allocated money shall only be utilised by the states for mitigation of drinking water problems in the habitations affected with arsenic and fluoride content, it said.

The guidelines suggest the states should take up "such habitations where the entire population is to be provided with safe drinking water", which should not be less than 8-10 litres per person. Purification plants would be set up with the grant while the cost of raw water and electricity would be borne by state governments.

State-wise allocation

State	Grant (₹ in lakh)
Punjab	3,935
Haryana	266
Uttarakhand	62
Jammu & Kashmir	47
Rajasthan	43,129
Telangana	9,051
Karnataka	5,990
Maharashtra	2,408
Bihar	2,283
Andhra Pradesh	2,126
Madhya Pradesh	1,585
Uttar Pradesh	1,339
Odisha	200
Jharkhand	150
Chhattisgarh	105
Total	72,676

गूगल मैपिंग से यमुना में गंदे पानी को रोकेंगे

हिं-2-4-16

नई दिल्ली | मुख्य संवाददाता

दिल्ली सरकार ने यमुना में सीवर और औद्योगिक कचरे के अलावा खतरनाक तत्वों के प्रवाह को रोकने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। इसके लिए उद्योगों से निकलने वाले खतरनाक तत्वों को नदियों में मिलने से रोकने के लिए यूरोप की तर्ज पर रिवर स्कैनिंग पद्धति को अपनाया गया है।

हाल ही में विश्व जल दिवस के अवसर पर जलबोर्ड और पर्यावरण विभाग की इस साझा पहल को अप्रैल में शुरू करने का प्रस्ताव है। काम बजट प्रस्ताव में आवंटित राशि के जारी होने का इंतजार किया जा रहा है।

बहुस्तरीय निगरानी सुनिश्चित हो सकेगी : योजना से जुड़े विशेषज्ञ संजय शर्मा ने बताया कि रिवर स्कैनिंग पद्धति से यमुना में मिलने वाले पानी की बहुस्तरीय निगरानी सुनिश्चित हो सकेगी। इसके लिए जलबोर्ड ने यमुना में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से शोधित पानी के अलावा उद्योगों से निकलने वाले खतरनाक तत्वों से युक्त गंदे पानी की यमुना में मिलावट को गूगल मैपिंग से पकड़ने की तैयारी कर ली है। उद्योग एवं सीवर लाइनों के अलावा अन्य स्रोतों से यमुना में मिलने वाले पानी की निगरानी के लिए रिवर्स मॉनीटरिंग सिस्टम मददगार बनेगा।

पहल

- रिवर स्कैनिंग पद्धति प्रदूषित पानी को रोकने में कारगर साबित होगी
- उन नालों की पहचान करेंगे, जिनके पानी से ज्यादा प्रदूषण

नालों की पहचान की जा सकेगी : इस प्रणाली के तहत गूगल मैपिंग की मदद से उन नालों की पहचान की जाएगी, जिनमें घरों से निकलने वाले गंदे पानी को जलशोधन संयंत्र से गुजारे बिना सीधे यमुनों प्रवाहित कर दिया जाता है। इससे यमुना में मिलने वाले गंदे पानी के स्रोत को पहचान कर उस संस्था या एजेंसी के खिलाफ जलबोर्ड सख्त कार्रवाई करेगा जिसकी उक्त नाले रोकने की जिम्मेदारी है। अगले एक साल में पूरा होने वाली इस योजना पर अनुमानित लागत 5 करोड़ रुपये बताई गई है।

पैसा लौटाएं नहीं, यमुना को साफ करें : एनजीटी

पीटीआई, नई दिल्ली : नैशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने शुक्रवार को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को आदेश दिया है कि वह पिछले फाइनेंशल ईयर में यमुना की सफाई के लिए आवंटित पैसे को दिल्ली सरकार को न लौटाए। ग्रीन ट्रिब्युनल ने यह भी साफ किया कि डीजेबी इस पैसे का इस्तेमाल इस साल यमुना की सफाई और 'मैली से निर्मल यमुना प्रोजेक्ट' को पूरा करने के लिए करे। एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, ''इस मामले की परिस्थतियों को देखते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि पैसा नहीं लौटाया जाएगा और वह 13 जनवरी, 2015 के मुख्य फैसले को पूरा करने के लिए खर्च किया जाएगा, जो डीजेबी के प्रस्ताव पर ही पूरी तरह आधारित है और उसे इस फैसले के तहत बनी प्रिंसिपल कमिटी ने स्वीकार भी किया है।'' एनजीटी ने यह निर्देश तब जारी किया जब डीजेबी के वकील ने इस बात की आशंका जताई कि नए फाइनेंशल ईयर के शुरू होने पर उसे पैसा लौटाना होगा। ऐसी स्थिति में बोर्ड के पास पैसे की कमी हो जाएगी जबकि ठेकेदारों को उनके किए गए कामों के लिए पैसा दिया जाना बाकी है। हालांकि एनजीटी ने डीजेबी को उससे परमिशन लिए बिना पैसे खर्च पर फटकार लगाई थी और आदेश दिया था कि एनजीटी से परमिशन लिए बिना एक भी पैसा न खर्च किया जाए।

दिल्ली जल बोर्ड को दिया आदेश

दिल्लीवालों को अप्रैल से ही झुलसाने लगी गर्मी

हि- 3-4-18

नई दिल्ली/एनसीआर | हिटी

दिल्ली वालों को अप्रैल में ही गर्मी झुलसाने लगी है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इसका एहसास देश के दक्षिणी भाग को पहले ही होने लगा था। अप्रैल शुरू होते ही गरम हवा और बढ़ते तापमान को उत्तर पश्चिमी भारत में महसूस किया जाने लगा है।

देश के दक्षिण और पश्चिमी हिस्से में मार्च के अंत में ही पारा 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के वरिष्ठ विज्ञानी महेश पलावत का कहना है कि पिछले साल अप्रैल में वर्षा की गतिविधि के कारण पारा ज्यादा नहीं चढ़ पाया था। इस बार पश्चिमी विक्षोभ या मानसून पूर्व वर्षा की ज्यादा संभावना नहीं है।

स्काईमेट के अनुसार, पिछले दो महीने भी गरम रहे हैं। अप्रैल के भी गरम दर्ज होने की संभावना है।

मौसम की मार

- गरम हवा और बढ़ते तापमान का असर दिखाई देने लगा
- बारिश न होने के चलते लगातार बढ़ता जा रहा तापमान

1200
वर्ग किलोमीटर जमीन थी 1901 में माजुली क्षेत्र की

540
वर्ग किलोमीटर में सिमट चुका है अब माजुली द्वीप

1601
परिवार गंवा चुके जमीन व घर 1975 से अब तक

गांव पिछले चार दशक में हो चुके हैं इस द्वीप से गायब

नाव स्टीमर ही एकमात्र विकल्प

इस द्वीप के लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि धरती के बाकी हिस्से से जुड़ने के लिए उनके पास एकमात्र विकल्प नाव या स्टीमर ही है। छोटी से छोटी जरूरत के लिए भी उन्हें नदी पार के जाना पड़ता है। महिलाओं, बुजुर्गों व बच्चों को खासतौर पर परेशानी होती है। बुनियादी सुविधाओं का बेहद अभाव है। बांस के पुल कभी भी बाढ़ में बह जाते हैं। रहने के लिए भी नावनुमा घरों में रहना पड़ रहा है। चुनावों से पहले सुविधाओं के कई सारे वादे तो किए जाते हैं, लेकिन ग्रामीणों के लिए स्थिति वही की वही रहती है।

माजुली में उठीं सियासी लहरें

माजुली, असम का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र। आबादी करीब 1.60 लाख, वोटर 1.07 लाख। ब्रह्मपुत्र नदी में बार-बार आने वाली बाढ़ के चलते इस क्षेत्र का अधिकतर हिस्सा कटाव में बह चुका है। यह देश के बाकी हिस्सों से अक्सर कटा ही रहता है। मगर देश के सबसे बड़े नदी द्वीप में इन दिनों अचानक से सियासी लहरें उछाल मारने लगी हैं। कारण, असम में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार व केंद्रीय खेल मंत्री सर्वानंद सोनोवाल इसी सीट से अपना भाग्य आजमा रहे हैं।

माजुली असम का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल भी है। लेकिन यहां बुनियादी सुविधाओं के लिए हर रोज जूझना पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी में आने वाली बाढ़ से लगातार माजुली का बड़ा क्षेत्र कटाव में बह जा रहा है। 1901 में जहां माजुली का क्षेत्र 1200 किलोमीटर तक था, वह अब घटकर 540 वर्ग किलोमीटर तक ही सिमट चुका है। आदिवासी परिवार नाव पर बने चलते-फिरते घरों में रहते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने सरकार से उम्मीद भी छोड़ दी है। लोग मजदूरी करने को मजबूर हैं।

'सपनों' के पुल का इंतजार

माजुली की सबसे बड़ी समस्या यह है कि मुख्य भूभाग से जोड़ने के लिए यहां कोई पुल ही नहीं है। हर रोज हजारों लोग स्टीमर पर सवार होकर माजुली से जोरहट जाते हैं। छोटी से छोटी जरूरत के लिए भी उन्हें नदी पार कर के जाना पड़ता है। अपने चुनावी वादों में सर्वानंद सोनोवाल माजुली द्वीप के लिए पुल बनवाने का वादा कर चुके हैं। अनुमान है कि इस पुल के निर्माण पर 10 हजार करोड़ तक खर्च आएगा। हालांकि भाजपा ने पुल का ऐलान कर दिया है, लेकिन उसके लिए फंड जारी नहीं किया। उधर, मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के अपने तर्क हैं। वह कहते हैं कि हम तो माजुली को हेरिटेज साइट मानते हैं, इसलिए छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। सोनोवाल चुनाव प्रचार के दौरान माजुली में लोगों को एक रुपये किलो की दर पर चावल देने का ऐलान कर चुके हैं। साथ ही वह माजुली के प्राकृतिक स्त्रोतों के बेहतर इस्तेमाल की बात करते हैं।

जनजातीय नायक

सर्वानंद असम के सोनोवाल कछारी नामक जनजातीय समुदाय से आते हैं। अगर वह मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो जोगेन हजारिका के बाद दूसरे जनजातीय मुख्यमंत्री होंगे। हजारिका 1979 में सिर्फ 94 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। सोनोवाल का जन्म 1962 में डिब्रूगढ़ के पास दिनजान में हुआ। फिलहाल वह असम के लखीमपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। एलएलबी तक पढ़ाई करने वाले सोनोवाल अविवाहित हैं। राज्य की राजनीति में तेजी से चमकने वाले सोनोवाल ने छात्र राजनीति से से करियर शुरू किया था। उन्हें जातीय नायक के तौर पर पुकारा जाता था। पांच साल पहले वह भाजपा में शामिल हुए।

भाजपा का दांव सोनोवाल पर

माजुली में सोनोवाल का मुकाबला कांग्रेस के वर्तमान विधायक राजीव लोचन से है। असम में भारतीय जनता पार्टी ने पर्याप्त समय पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि राज्य में हमारी सरकार बनी तो सर्वानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री होंगे। असम की राजनीति में वह एक ऐसा चेहरा हैं, जिस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। कभी किसी विवाद में नाम नहीं आया। वह भाजपा के लिए असम के स्टार प्रचारक हैं।

असम के हर जिले की राजनीति को बेहतर समझने वाले सोनोवाल लोगों की नब्ज को पकड़कर उसके मुताबिक संवाद करते हैं। साल 2014 में जब केंद्र में भाजपा सरकार बनी तो सर्वानंद सोनोवाल को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर को तरजीह देने की नीति का ऐलान किया। यही नहीं केंद्र में पूर्वोत्तर के प्रतिनिधित्व का खासतौर पर ख्याल रखा गया। सर्वानंद सोनोवाल बांग्लादेशी शरणार्थियों के मुद्दे पर 'जीरो टौलरेंस' का विचार रखते हैं।

काला कारोबार : एक समय पर पांच जेसीबी और दर्जन ट्रैक्टर से हो रहा कुंदा में खनन

छलनी कर दी जीवनदायिनी

4-4-16

पत्रिका

मुहिम

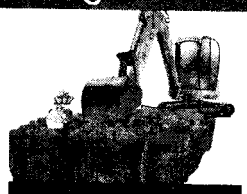

खनन पर लगे रोक

कब्रिस्तान के पीछे इस तरह दिनदहाड़े जेसीबी मशीन से कुंदा नदी की खुदाई की जा रही है।

खरगोन @ पत्रिका

mp.patrika.com

खरगोन की जीवनदायनी कुंदा नदी को रेत माफियाओं ने छलनी कर दिया। यह खनन भी प्रशासन की नाक के नीचे बीच शहर में हो रहा है। पत्रिका टीम ने जब कब्रिस्तान के पीछे स्थित नदी का मुआयना तो खनन का भयानक चेहरा सामने आया। यहां करीब पांच सौ से अधिक गड्ढे कर रेत निकाली जा रही है। करीब पांच जेसीबी और एक दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली खनन के इस काम को अंजाम दे रहे हैं। प्रशासन की नाक के नीचे हो रहे खनन पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। जिस गति से यहां खनन हो रहा है उससे अगली ही बारिश में नदी तटबंध छोड़कर यहां बनी कॉलोनियों को डुबो देगी।

दिन दहाड़े नदी से बेखौफ तरीके से अवैध रेत का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। यहां जिस गति से खनन हो रहा है, उससे नदी किनारे की बस्तियों के अस्तिव पर संकट खड़ा हो गया है। अनुमान के मुताबिक प्रतिदिन 100 से 150 ट्रॉली रेत निकाली जा रही है। इतनी बढ़ी मात्रा में रेत निकलने से नदी में बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। खनन के कारण नदी के पाट चौड़े हो गए हैं।

किसी का खौफ नहीं

नर्मदा या अन्य सहायक नदियों से आमतौर पर रेत माफिया रात में अवैध उत्खनन कर रेत परिवहन करते हैं, लेकिन शहर में रेत के कारोबार से जुड़े माफियाओं को कार्रवाई का जरा भी डर नहीं है। यही कारण है कि शहर की किसी भी सड़क अथवा चौराहे से दिनभर रेत से भरे ट्रैक्टर जब गुजरते हैं, तो उन्हें रोकने की कोई हिम्मत नहीं करता। पिछले छह महीनों से खनिज और राजस्व विभाग ने मिलकर कोई बड़ी कार्रवाई रेत परिवहन करने वाले ट्रैक्टरों के खिलाफ नहीं की।

कार्रवाई कराएंगे

कहां और किसकी अनुमति से रेत से खनन हो रहा है मैं दिखवाता हूं। खनिज अधिकारी और राजस्व अधिकारियों को भेजकर करवाएंगे।

नीरज दुबे, कलेक्टर

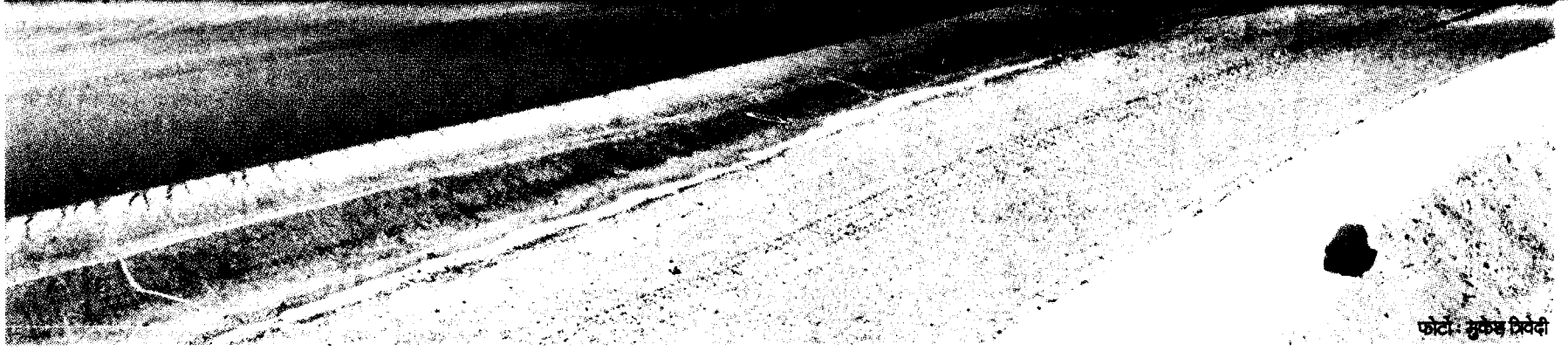

फोटो : मुकेश त्रिवेदी

नदी किनारे भी लोग प्यासे

नदी के बदले तापी अब नाले के रूप में, सूरत शहर में गर्मी के साथ ही पानी की किल्लत शुरू

नियमित आपूर्ति नहीं, प्रेशर भी कम, प्रशासन का दावा - पानी पूरा, एहतियात जरूरी

सूरत @ पत्रिका

patrika.com/city

गर्मी की शुरुआत के साथ ही तापी नदी के किनारे बसे शहर में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। कई जोन में पानी की सप्लाई में दिक्कत आ रही है तो कम प्रेशर से पानी आने की शिकायतें भी आ रही हैं। शहर की लाइफलाइन तापी इन दिनों वेंटिलेटर पर है। नदी से नाले में तब्दील होती तापी में पानी की कमी की वजह से इसके किनारे रह रहे कई लोग प्यासे हैं। उधर, मनपा प्रशासन का दावा है कि तापी में जरूरतभर का पानी है और आपूर्ति में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन देश के अन्य शहरों में पानी की हालत को देखते हुए इसकी बचत के लिए एहतियात बरतने की जरूरत है।

प्यास बुझाने के लिए लोग शहर के बीच से गुजर रही तापी नदी पर निर्भर हैं। शहर की जीवनरेखा बन चुकी तापी इस वक्त खुद अपने लिए संघर्ष कर रही है। लोग कहने लगे हैं कि किनारे छोड़ कर नाले की तरह बह रही तापी को वेंटिलेटर की जरूरत है। शहर की जलापूर्ति उकाई बांध से छोड़े जा रहे पानी पर निर्भर है। हालांकि मनपा के हाईड्रोलिक विभाग का दावा है कि तापी में पर्याप्त पानी है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उधर, शहर के लोगों का आरोप है कि कई जगह पानी की आपूर्ति नियमित नहीं है। वराछा हो या रांदेर लोगों को पानी के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। कमोबेश यही हालत डिंडोली-गोडादरा के कुछ इलाकों में है। कई जगह पानी मिल रहा है, तो प्रेशर पूरा नहीं है। इससे आपूर्ति के दौरान दिनभर की जरूरत के लिए पानी का पर्याप्त संग्रहण लोगों के लिए चुनौती बना हुआ है। हाईड्रोलिक विभाग के मुताबिक उसने समर पॉलिसी बना ली है और लोगों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

होली ने बढ़ाया संशय

हाईड्रोलिक विभाग हर बार होली पर अतिरिक्त पानी की आपूर्ति करता है। इस बार मनपा ने होली पर लोगों को अतिरिक्त पानी मुहैया नहीं कराया। हाईड्रोलिक विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पानी संकट को देखते हुए मनपा ने पहले ही सूखी होली का आह्वान किया, इसलिए इस बार अतिरिक्त पानी नहीं दिया गया। होली पर अतिरिक्त पानी नहीं मिलने से लोगों में यह संदेश गया कि पानी का संकट है। अनियमित आपूर्ति और कम प्रेशर ने भी इस संशय को बढ़ा दिया। हाईड्रोलिक विभाग के मुताबिक जब भी उकाई से पानी छोड़ा जाता है, उसके प्रोसेस में मनपा को दिक्कत आती है। पानी के साथ बहकर आने वाली जलकुंभी और अन्य जलीय वनस्पतियां प्लांट में अटककर पानी के प्रोसेस की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। इस कारण तात्कालिक तौर पर पानी का अस्थाई संकट उत्पन्न हो जाता है। जलकुंभी हटाकर साफ करने के बाद प्रोसेस शुरू होते ही पानी का यह अस्थाई संकट दूर हो जाता है।

पानी की दिक्कत पर अधिकारी तलब

पानी की शिकायतों को लेकर मनपा की स्थाई समिति में गुरुवार को हाईड्रोलिक विभाग के अधिकारियों को तलब किया गया। अधिकारियों से कहा गया कि गर्मी में लोगों को पानी की आपूर्ति को लेकर दिक्कत नहीं हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाने की तैयारी पहले से कर ली जाए। स्थाई समिति अध्यक्ष राजेश देसाई ने अधिकारियों से गर्मी से पहले की तैयारियों पर पूरी जानकारी ली। वियर कम कोजवे के स्तर को बहाल रखने के लिए सिंचाई विभाग काकरापार से पानी रिलीज कर रहा है। तापी में आ रहे इस पानी के साथ वनस्पतियां भी आ रही हैं। इससे पालिका इनटेक वेल में तकनीकी खामियां आने लगी हैं। कई जगह लाइन में गड़बड़ी की वजह से प्रेशर की कमी की शिकायत है। वराछा मेन रोड पर मुख्य पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने से पिछले दिनों तीन जोन की बड़ी आबादी को पानी के संकट से जूझना पड़ा था। स्थाई समिति अध्यक्ष ने बताया कि कतारगाम गामतल क्षेत्र में गंदा पानी और पानी के कम दबाव के पीछे 35 से 40 साल पुरानी लाइन मुख्य वजह है। समिति अध्यक्ष ने विभागीय अधिकारियों से शहर में पानी के टैंकरों की संख्या और ड्राइवरों के बारे में जानकारी मांगी है, जिससे जरूरत पड़ने पर लोगों को टैंकर से पानी मुहैया कराया जा सके।

रूल लेवल मेंटेन करना जरूरी

अधिकारियों के मुताबिक पानी की बेहतर गुणवत्ता के लिए कोजवे पर रूल लेवल मेंटेन करना जरूरी है। बेहतर गुणवत्तायुक्त पानी के लिए कोजवे पर पांच मीटर से अधिक का रूल लेवल रहना चाहिए। फिलहाल यह लेवल 4.86 मीटर है। मनपा प्रशासन ने सिंचाई विभाग को इसे 5.5 मीटर पर मेंटेन रखने के लिए कहा है। मनपा प्रशासन का मानना है कि जल संचय के लिए लोगों में जागरूकता जरूरी है। देशभर में इन दिनों पानी का संकट है। जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी, यह संकट और गहराएगा। यदि समय रहते पानी बचाने पर ध्यान नहीं दिया तो सूरत में भी लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ सकता है।

पर्याप्त है पानी

शहर में पानी की कोई कमी नहीं है। जितनी मांग है, उसके अनुरूप पानी की आपूर्ति की जा रही है। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि इसे व्यर्थ नहीं बहने दिया जाए। जरूरतभर का पानी इस्तेमाल किया जाए तो भविष्य में दिक्कत से बचा जा सकता है। कुछ जगह प्रेशर की शिकायत मिलती है तो उसे तुरंत दुरुस्त कर दिया जाता है।

के.एच. खटवाणी
एडीशनल सिटी इंजीनियर, सूरत मनपा

...ned at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

- रविवार को पारा 39.4 डिग्री तक पहुंचा, मौसम विज्ञानियों ने आज बारिश की संभावना जताई

गर्मी ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ा

हि. हिं-4-4-16

आफत

नई दिल्ली | प्रमुख संवाददाता

अप्रैल की शुरुआत में ही गर्मी ने पिछले पांच वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रविवार को अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से छह डिग्री सेल्सियस अधिक है। पांच वर्षों में इस दिन कभी भी इतना तापमान नहीं रहा।

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार सुबह दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। सुबह से ही आसमान में बादल दर्ज किए जाएंगे। दिल्ली व एनसीआर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने की संभावना है।

रविवार को न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा। यह भी सामान्य से छह डिग्री सेल्सियस अधिक है। पालम में पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यहां न्यूनतम तापमान भी 25.1 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया। दिल्ली में आर्द्रता का अधिकतम स्तर 73 फीसदी दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के वैज्ञानिक एके बंसल के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके चलते सोमवार को मौसम में बदलाव दर्ज किया जाएगा। दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, चंडीगढ़, झारखंड समेत कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। जम्मू-कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में बारिश दर्ज किए जाने की भी संभावना है।

इंडिया गेट पर रविवार को तेज धूप से बचने की कोशिश करती महिला। • सोनू मेहता

पिछले पांच वर्षों में 3 अप्रैल का तापमान

वर्ष	तापमान (डिग्री सेल्सियस)
2011	34
2012	38
2013	34
2014	33
2015	33
2016	39.4

45.6° तक जा चुका है पारा

अप्रैल महीने का सबसे अधिक तापमान 1941 में दर्ज किया गया था। इस वर्ष अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस तक चलाया गया था।

गर्मी की मार जारी रहेगी

मौसम के जानकारों के अनुसार इस वर्ष अलनीनो के प्रभाव के चलते सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने की आशंका है। अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस तक अधिक रह सकता है। हालांकि जुलाई में अच्छी बारिश का अनुमान है।

पहली नजर...

20 देश शामिल होंगे 'भारत जल सप्ताह' में

नई दिल्ली, (ब्यूरो) : जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत जल सप्ताह का चौथा संस्करण सोमवार से चार दिन तक यहां तक आयोजित करेगा। इसकी घोषणा करते हए केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने कहा कि इस वर्ष के भारत जल सप्ताह का विषय 'सबके लिए जल : सम्मिलित प्रयास' है। उन्होंने बताया कि इस्राइल भागीदार देश के रूप में इस विशाल आयोजन से संबद्ध होगा। उन्होंने कहा कि भारत जल सप्ताह के पहले दिन उद्घाटन सत्र के बाद पूर्ण सत्र और राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों की बैठक होगी। भारत समेत करीब 20 देशों के 1500 प्रतिनिधि इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम प्रगति मैदान में आयोजित होंगे। इसके अलावा प्रगति मैदान के हॉल नम्बर-9 में 'वॉटर एक्सपो-2016' का आयोजन किया किया जा रहा है, जिसमें जल संसाधन क्षेत्र की प्रौद्योगिकियों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा।

जल संरक्षण के लिए विधेयक लाएगी सरकार

नई दिल्ली, (वार्ता): देश के विभिन्न हिस्सों में भू-जल के खतरनाक स्तर तक गिरने से चिंतित केंद्र सरकार जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विधेयक लाने पर विचार कर रही है।

जल संसाधन और नदी विकास मंत्री उमा भारती ने सोमवार से शुरू हो रहे पांच दिवसीय चौथे भारत जल सप्ताह 2016 के बारे में जानकारी देने के वास्ते आज यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में कहा कि जल संचय भविष्य की बड़ी जरूरत है और सरकार इसके लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है।

उन्होंने कहा कि विधेयक में वर्षा जल के संरक्षण के साथ ही भूजल

के संरक्षण को भी सुनिश्चित किया जाएगा और यह काम राज्यों के साथ मिलकर किया जाएगा।

उनका कहना था कि जल भले ही राज्यों का मामला है लेकिन जल की चिंता पर उनकी सहमति से कानून बनाने पर विचार किया जा सकता है। उनका कहना था कि इस मामले में राज्यों के अधिकारों का किसी भी स्तर पर उल्लंघन नहीं किया जाएगा लेकिन यदि उन्हें केंद्र की मदद चाहिए तो इसके लिए उन्हें पूरा सहयोग दिया जाएगा।

सुश्री भारती ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में भूजल स्तर 70 प्रतिशत तक नीचे पहुंच चुका है। यह गंभीर स्थिति है और इससे निबटने के लिए जल संरक्षण को महत्व दिया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे जल सप्ताह में भूजल के स्तर को बढ़ाने के मामले में विशेष रूप से मंथन किया जाएगा।

40 डिग्री के पार टेंपरेचर

■ नगर संवाददाता, नई दिल्ली

आज शाम बारिश होने की संभावना

अप्रैल में ही गर्मी कड़े तेवर दिखाने लगी है। शनिवार को कई इलाकों में तापमान 38 डिग्री से ज्यादा दर्ज हुआ। पालम में मैक्सिमम टेंपरेचर 41.2 डिग्री चला गया, जो नॉर्मल से 6 डिग्री ज्यादा है। सफदरजंग में मैक्सिमम टेंपरेचर नॉर्मल से पांच डिग्री ज्यादा के **साथ** 38.9 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले छह सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही तापमान 40 डिग्री पार कर गया है। आने वाले दिनों में बढ़ते तापमान से राहत मिलने के चांस कम हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने हीट वेव चलने की भी आशंका जताई है।

मौसम विभाग ने अपने बुलेटिन में कहा कि संडे को बादल छा सकते हैं। शाम के वक्त दिल्ली और आसपास के मैदानी इलाकों में बारिश होने की उम्मीद है। मैक्सिमम टेंपरेचर 40 डिग्री और मिनिमम टेंपरेचर 22 डिग्री रहने का अनुमान है। शनिवार को मिनिमम टेंपरेचर नॉर्मल से तीन डिग्री ज्यादा के साथ 21.5 डिग्री दर्ज हुआ। हवा में मैक्सिमम ह्यूमिडिटी 74 पर्सेंट दर्ज हुई। नैशनल वेदर फोरकॉस्टिंग सेंटर के हेड बी.पी.यादव ने बताया कि दिल्ली में अप्रैल में तापमान ज्यादा रहने की संभावना है। मौसम के सिस्टम का असर कम रह सकता है। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की आशंका है। स्काइमेट के मौसम वैज्ञानिक महेश पलावत ने बताया कि दिल्ली में अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही पिछले छह सालों की तुलना में मैक्सिमम टेंपरेचर 40 डिग्री के पार कर गया है। आमतौर पर अप्रैल के दूसरे या तीसरे हफ्ते में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा दर्ज होता है। लेकिन इस बार कोई भी वेदर सिस्टम के एक्टिव न होने से तापमान ज्यादा दर्ज हुआ है। राजस्थान और पाकिस्तान में मौसम बिलकुल ड्राई है। इस वजह से दिल्ली की तरफ भी बिल्कुल ड्राई हवा दस्तक दे रही है।

and documented at [illegible] (English) & Publicity Section [illegible]

पहली बार भविष्यवाणी : मौसम विभाग ने कहा, अलनिनो और ग्रीन हाउस गैस का असर

अप्रेल से जून तक जमकर पड़ेगी गर्मी

नई दिल्ली. पहली बार मौसम विभाग ने परिस्थितियों के आधार पर अनुमान लगाया है कि इस साल जबरदस्त गर्मी पड़ेगी। देश में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। इसके साथ ही भारत के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में लू की आशंका है। मौसम विभाग ने पहली बार गर्मी और लू को लेकर भविष्यवाणी की है। विभाग का कहना है कि अप्रेल से जून तक देश में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा।

ग्रीन हाउस गैस जिम्मेदार : पिछले साल गर्मी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2500 से ज्यादा जानें गई थीं। मौसम विभाग के अनुसार लू की प्रचंडता और अवधि पूरे देश में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जिसके लिए ग्रीन हाउस गैसें काफी हद तक जिम्मेदार हैं।

इन राज्यों में प्रचंड लू

अप्रेल से जून तक दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओड़ीशा, तेलंगाना, मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय आंध्र प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक होने और मध्यम से प्रचंड लू की ज्यादा आशंका है।

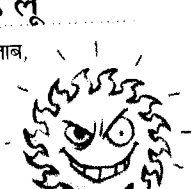

अब से हर 5वें दिन जारी होगी चेतावनी

मौसम विभाग एक अप्रैल से हर पांचवें दिन पूरे देश में गर्मी और लू की स्थिति पर चेतावनी भी जारी करेगा। गर्मी सम्बंधी भविष्याणी की वैधता 15 दिनों की होगी और यह विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से प्रकाशित

वर्ष : 11 . अंक : 271, पत्रिका समाचार पत्र समूह : 8 राज्य, 37 संस्करण

Wait over, Naini Lake in North Delhi to finally get a facelift

HT Correspondent, Hindustan Times, New Delhi | Updated: Apr 02, 2016 00:06 IST

The Delhi government will soon launch a much-awaited revamp of Naini Lake in Model Town in North Delhi. (Vipin Kumar/HT Photo)

Share 2 Share Share Share

The Delhi government will soon launch a much-awaited revamp of Naini Lake in Model Town in North Delhi.

North Delhi Municipal Corporation mayor Ravindra Gupta on Friday met Delhi government's tourism minister Kapil Mishra and discussed rejuvenation plans of Naini Lake that has been pending for close to a year now.

Sources in the government later said that during the meeting it was decided that Delhi Tourism will work to rejuvenate Naini Lake for boating and other such activities.

Last year, the Delhi government had decided to beautify the lake in a natural manner and revive it ecologically. The plan did not, however, take off instantly as the lake comes under the North Delhi Municipal Corporation's purview but was being maintained by the Delhi tourism department.

The roadblock in terms of agreement between the two bodies was finally cleared on Friday, both the corporation and government officials said.

Behind the final agreement is a long campaign for the ecological rejuvenation of Naini

Lake, and 600 other water bodies in the city.

Residents of Model Town had got together and formed a pressure group that raised awareness and also organised street plays and signature campaigns for the revamp plan to be implemented.

The plan of ecological rejuvenation was developed by ecologist CR Babu. It included introducing specific plants, insects and animals in the lake to clean it and increase the biodiversity. It also forbid concretisation and restricted water sports.